>

Title: Need to expedite enactment of Delhi Apartment Act.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, दिल्ली से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे मैंने अभी सबमिशन में भी उठाया था। दिल्ली का बढ़ता हुआ स्वरूप है और अब लोग यहां कोठियों के बजाए अपार्टमैंट्स बना रहे हैं। जो नक्शे से बन रहे हैं, वे अपार्टमैंट्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। उन अपार्टमैंट्स में तकरीबन 25 से 30 लाख लोग रहते हैं। आज सिर्फ इस वजह से लाखों मुकदमे हो रहे हैं क्योंकि उनकी खरीद और बेच नहीं हो सकती, वे सिर्फ पावर ऑफ अटार्नी पर ट्रांसफर होते हैं। उनका झगड़ा बिल्डर से भी होता है, जहां लीज़ बनी होती है, कि ग्राउंट रैंट कौन देगा, इसके ऊपर मुकदमे चलते रहते हैं। पहले भी कई बार मांग हुई है। आदरणीय मंत्री जी बॉय चांस यहां बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अपार्टमैंट बिड आनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

वह बहुत ओवर ड्यू हो गया है। उसकी बहुत सख्त जरूरत है। लोग बड़े पीड़ित हैं, परेशान हैं। वे मुकदमे-बाजी में लगे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा कोई डायरेक्टिव देंगी या मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वे कुछ आश्वासन दे दें, जिससे दिल्ली वालों को कुछ राहत मिल जाये। हमारे पास अपनी स्टेट नहीं है, इसलिए हमें बार-बार यहां आना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी आज कुछ न कुछ राहत दे देंगे।